VNK-YSR/5.00/3O

श्री अरुण जेटली (क्रमागत) : उसके साथ छेड़छाड़ कभी आपने की हो या कभी हमने की हो, मेरी जानकारी में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। जब नई सीरीज़ बनती है और यह 2011-12 से बनती है। जब यह बनती है, तो उस साल की जो विकास दर होगी, वह विकास है। Growth is growth. पिछले साल की तुलना में वह कितना आगे बढ़े हैं, वह उसको रिफ्लेक्ट करती है। सच में, एक समय आ गया था कि हमारी जो credibility थी, विश्वसनीयता थी, जो 90 के दशक में बनी थी, वह पूरे विश्व में भी और देश में भी धीरे-धीरे कम होती गई। कारणों में मैं नहीं जाता, लेकिन निर्णय प्रक्रिया ढीली हो गई, सुधार होने अपने आप में बंद हो गए।

आपने चिंता व्यक्त की कि क्या fiscal deficit में slippage हो सकता है? आज तो केवल marginal slippage की टिप्पणी आती है, उस वक्त तो बहुत बड़ा slippage हुआ था और slippage इतना कि उसका Current Account Deficit पर क्या असर था, साढ़े चार परसेंट से ज्यादा Current Account Deficit था। आपका fiscal deficit 6 परसेंट के करीब पहुंच रहा था। इसलिए आप यह न भूलिए कि पिछले साढ़े तीन, चार सालों में उस 4.6 परसेंट fiscal deficit को धीरे-धीरे नीचे लाना और उसको एक प्रकार से उस glide path के ऊपर ले आना, यह consistently पिछले तीन वर्षों में हम लोगों ने किया है।

जिस तरह का fiscal prudence, fiscal discipline था, उसका उदाहरण भी दिया है और वह स्वाभाविक भी है, इसलिए जो बाजार हैं, वे उस fiscal discipline को

reward करते हैं। उस विश्वसनीयता का असर भी पड़ा है। दुनिया की परिस्थिति क्या थी? ये दो, तीन, साढ़े तीन, चार साल से, जिनमें दो साल देश में सूखा भी था, दुनिया की ग्रोथ नीचे जा रही थी। इस चौथे वर्ष में थोड़ी सी pick up करनी शुरू की है और इस बार 3.6 परसेंट global growth की उम्मीद की जा रही है। इस स्टेज पर अर्थव्यवस्था के अंदर बड़े structural reforms लाना, मैं अगर आपसे एक शिकायत करूं कि इनमें कई ऐसे हैं, जिनके लिए आपने भी प्रयास किए थे, वे किसी कारणवश नहीं हो पाए। हममें तो कम से कम इतनी ईमानदारी थी, आधार तो आपने शुरू किया था। Unique Identity Number तो आपकी सरकार का एक idea था। आरंभ में कई बार हम लोगों को कठिनाई थी, क्योंकि हमारे कई साथियों के मन में एक विषय आता था कि क्या non-citizens को यह मिलेगा, क्या citizen or non-citizen के बीच में जो अंतर है, वह इसकी वजह से धूमिल हो जाएगा? लेकिन पहले ही महीने में नंदन नीलेकणि, जो आपकी सरकार में इस विषय को देखते थे, उन्होंने आकर प्रेजेंटेशन दी और इसके लाभ बताए, तो प्रधान मंत्री जी में इतनी openness थी कि उन्होंने पहली ही मीटिंग के बाद, दो घंटे की presentation के बाद कहा कि इस idea को आगे ले जाने की आवश्यकता है। उसको statutory support देना, फिर केन्द्र और राज्य सरकार अपनी हर योजना.... हर साल बजट के बाद शाम को क्या चर्चा होती थी? चर्चा यही होती थी कि subsidies must be targeted. Subsidy must benefit the poor. Subsidies cannot be an unidentified amount reaching an unidentified section of people. हम बीसियों साल से चर्चा कर रहे थे। पहला कदम आपने उठाया, उसको आप पूरा नहीं

कर पाए। हम लोग उसको उसके logical end पर ले गए और अब आपने उसके प्रति अपना रवैया बदल दिया। यह बड़ा structural change था। इसका लाभ भी हुआ है।

(3पी/एनकेआर-वीकेके पर जारी)

NKR-VKK/3P/5.05

श्री अरुण जेटली (क्रमागत) : आज किसी भी योजना में पैसा कम खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी targeting उस दिशा में सुधर गई है, वहां पहुंचने लगी है। आप जी.एस.टी. का उदाहरण देते हैं। यदि कहें तो वह सारे सदन का एक प्रकार से सामूहिक idea था। वाजपेयी जी की सरकार में केलकर कमेटी appoint हुई। उसके बाद आपकी सरकार ने उसकी घोषणा की। संविधान संशोधन बिल आप लाए। उसके बाद Empowered Committee बनी। Empowered Committee में लोगों को कुछ शंकाएं थीं। जो काम अधूरा रह गया था, उसे हमने पूरा करके, कानून को पारित किया। आप देखिए कि सदन के बाहर क्या तर्क देते हैं और सदन के बीच में क्या तर्क देते हैं ? सदन के बाहर आप कहते हैं कि रेट कम कीजिए और सदन के भीतर कहते हैं कि देखिए, revenue गिर रहा है। आप देखें कि पहले standard rate क्या था? मैं केवल standard rate की बात कर रहा हूं, कम-ज्यादा रेट वाली बात नहीं कर रहा हूं। पहले standard rate था - 12.5 परसेंट (केन्द्र) और 14.5 परसेंट (राज्य) at an average. अगर inter-state transaction है, तो CST लगता था, जिसका cascading effect जाकर 31 परसेंट पड़ता था। सालों तक वह 31 परसेंट रेट चलता रहा। केवल उसमें excise component छिपा रहता था, स्पष्ट होकर सामने नहीं आता था। फिर सामूहिक

रूप से तय हुआ कि उसकी placement 28 परसेंट में कर दी जाए। दो-तीन महीने के बाद GST Council को लगा कि collection अपेक्षाकृत ठीक नहीं हुआ है। उसमें केवल एक ही प्रश्न-चिह्न था कि IGST component ज्यादा था, जिसका division होता है। इसलिए 28 परसेंट वाले अधिकतर items या luxury या दूसरे negative products थे, उन 3-4 items को छोड़कर, बाकी को हमने धीरे-धीरे 18 परसेंट पर लाना शुरु किया। आपकी पार्टी यह मांग करने में सबसे आगे थी। शुरू में दो-तीन महीने उसका असर होगा, फिर उसके बाद अंतर दिखाई देगा। यह structural reform है, structural reform करने के क्या परिणाम होंगे, महीने -दो महीने के लिए आलोचना भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद व्यवस्था को लाभ होगा। यह स्वाभाविक है। Demonetization के पीछे भी यही भावना थी। यह ऐसी अर्थव्यवस्था थी, जिसमें cash economy अधिकतर चलती रहे, देश digitization की तरफ आगे बढ़े, cash component थोड़ा compressed हो और tax-base बढ़े। पहले सारी दुनिया आलोचना करती थी कि इस देश का tax base बहुत narrow है। कुछ संकेत सामने भी आ रहे थे। इन सब structural changes के बाद, उस दृष्टि से सबने सहयोग किया, जिसके कारण हम Insolvency and Bankruptcy Code भी ला पाए। इतने बड़े changes करने के बाद स्वाभाविक है कि एक-दो-तीन quarters में structural changes का असर पड़ सकता है। जब दुनिया धीमी गति से चल रही थी तो आनन्द जी, यहां इतनी खराब स्थिति नहीं थी कि देश-दुनिया के साथ हम भी डूब रहे थे। कम-से-कम इतिहास में पहली बार 3

साल लगातार आप दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने। चौथे वर्ष भी, इन सब structural changes के बाद, आपने कहा कि अर्थव्यवस्था बहुत धीमी है, जबकि इस साल World Bank कहता है कि by 0.1 per cent, you may be the second highest. अब साल के अंत में क्या होता है, मैं नहीं जानता।

(3Q/DS द्वारा जारी)

DS-RL/5.10/3Q

श्री अरुण जेटली (क्रमागत) : इसलिए आप देखें कि इन सबकी वजह से यह विश्वसनीयता वापस आयी है कि आज 13-14 साल के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को अपग्रेड मिला है। ये इतने सरल नहीं होते। देखिए, इसको आप इतना आसान मत समझिए। आप तो 'Fragile Five' के अंदर हिन्दुस्तान को छोड़ कर गए थे। यह phrase भारत के लिए यूज़ हुआ था। उस वक्त तो चिन्ता नहीं थी ! अगर 'Fragile Five' से अर्थव्यवस्था को upgrade मिलता है, तो देश में शायद कोई अच्छे काम हुए होंगे, तभी तो यह अपग्रेड मिला है ! Ease of Doing Business में आप तो 188 देशों में 142वें नम्बर पर छोड़ कर गए थे। देश की व्यवस्थाएँ बदलनी थीं। अगर हम तीन साल में उस 142 से 100 पर पहुँच जाते हैं, तो उसको आप और कुछ मानते हैं। इसका जो असर है, आपको मालूम है। अगर आप इन दिनों को देखें, तो मैं आज भी यह नहीं कह रहा कि हमारी सारी चुनौतियाँ समाप्त हो गईं, लेकिन अभी आपने कहा कि देश के अंदर एक्सपोर्ट की चिंता थी। यह स्वाभाविक है कि जब विश्व की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, तो खरीददार कम खरीददारी करेंगे। तब भारत का सामान क्या, दुनिया का

सामान भी कम बिकेगा और जब दुनिया का सामान कम बिकेगा, तो एक्सपोर्ट धीमा होगा। लेकिन, इस साल एक्सपोर्ट का आँकड़ा बदला जा रहा है। From April to November, you are already in the 11 to 12 per cent growth bracket. आप सितम्बर और नवम्बर का डेटा देख लीजिए। हालाँकि मैं यह नहीं कहता कि इसकी बड़ी consistency है। सितम्बर और नवम्बर में high growth हुई है और अक्टूबर में maintain हुई है। इस बार तो लगभग 30 परसेंट के करीब बढ़ी, सितम्बर में 26-27 परसेंट के करीब बढ़ी। इसमें core sector growth का latest figure 6.8 परसेंट आया है। कल मैं देख रहा था, Manufacturing PMI अपने आपमें 54.7 के करीब है। इसलिए इन सारे ट्रेंड्स को हम धीरे-धीरे समझें कि अगर यह एक प्रकार का ट्रेंड आता है, तो इसमें एक चीज की स्पष्टता आती है कि यह ट्रेंड 7.4 परसेंट, 8 परसेंट, 7.1 परसेंट क्यों आ रहा है।

उसके बाद हम लोगों ने structural reforms किए। स्वाभाविक है कि structural reforms की एक कीमत होती है। वह अपने आपको bottom out करती है और उसके बाद फिर वह आपका term use करने लगता है। मैं कम से कम यह कह सकता हूँ कि अब अपने आप में उसके संकेत आने आरम्भ हुए हैं। वहीं एक विषय आपने कहा कि सरकार का infrastructure में जो निवेश है, इस साल बजट में ही केवल 3.96 लाख करोड़ है। कोई social sector ऐसा नहीं है, जिसमें हमने इसे कम किया हो। आप केवल MNREGA का उदाहरण दे रहे थे, फूड के ऊपर, 1.45 लाख करोड़। यह कानून

आप लाए थे। जितने भी quick data आते हैं, वे अपने आपमें उस संकेत को स्पष्ट रूप से दिखला रहे हैं कि उसमें bottom out करके उसका curve सुधर रहा है।

Inflation management का अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत असर पड़ता है। यह आपके अंतिम वर्षों में 9 परसेंट, 10 परसेंट, 11 परसेंट तक भी गई थी। आज हमारी सरकार के peak period की inflation है, जो 4 परसेंट से ऊपर गई है। अब तो Monetary Policy Committee ने एक statutorily fixed target रखा है और वह statutorily fixed target 4 परसेंट प्लस/माइनस 2 का है। उसमें यह 2 परसेंट तक नीचे जाती रही है। इसके आज नीचे जाने के पीछे एक कारण तेल की कीमत है, इसके अलावा Seventh Pay Commission के House Rent Allowances अभी release हुए हैं और इन दिनों थोड़ा vegetable prices का अपने आपमें बढ़ना और Foreign Exchange Reserves, ये भी कारण हैं।

(3आर/एमसीएम पर जारी)

MCM-KR/3R/5.15

श्री अरुण जेटली (क्रमागत) : आपने कहा कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट जिस कैपिटल फॉर्मेशन पर आपने कहा जो चैलेंजिंग था पिछले क्वार्टर का डेटा, अगर आप देखें तो दोबारा से पॉजिटिव टेरिटरी में 4.7 परसेंट के करीब आना शुरू हुआ है और उसी तरह से जितने ये अपने आप में आंकड़े हैं आज के नॉन फूड क्रेडिट, 10 और 11 परसेंट के बीच में, जब पिछले महीने का आंकड़ा आया है तो इसलिए चैलेंजिंग रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे उस स्थिति में यह पूरे विश्व की स्थिति रही,

लेकिन उसका एक असर हिन्दुस्तान के ऊपर जो पड़ा, हम कंसिस्टेंटली 7 परसेंट से 8 परसेंट तक के ग्रोथ रेट और हम एकमात्र अर्थव्यवस्था थे, जो इस चुनौती काल में उस 7 से 8 परसेंट तक की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंदर अपने आपको मेन्टेन करना है। इस अवधि में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट धीरे थी, हमने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाई और यह जो साढ़े सात, आठ परसेंट की ग्रोथ रेट आई, उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट का रोल था और फॉरेन डॉयरेक्ट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हम सबसे बड़े रेसिपिएंट बन गए। इस साल भी अगर हम पहले दो क्वार्टर्स को देख लें तो यह 37 बिलियन के करीब है और इसलिए यह दोनों मिलाकर और अब तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के भी आरंभिक संकेत अपने आप में आने शुरू हो गए। इस परिस्थिति में सरकार की योजनाओं का इस देश के अंदर बहुत ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट डेटा आता है हर बार, ऐसी स्थिति में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज़ होता है, लेकिन इस चुनौती को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अपनी योजनाएं भी उसी दृष्टि से बनाई थीं। आपने कहा कि बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम के सामने, अपने यहां दो-तीन दिन पहले प्रश्न-काल में चर्चा की थी। आज हम सारे साधन लाकर बैंकिंग सिस्टम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार यह करते हुए बहुत विचित्र स्थिति है कि उद्योग के कुछ लोग बैंक का पैसा न दें और हमें टैक्सपेयर्स का पैसा इसलिए बैंक में डालना पड़े। यह जो बेलआउट हम लोग कर रहे हैं, यह अपने आप में बहुत आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन चूंकि पब्लिक सैक्टर बैंक सरकार की मिल्कियत के हैं , इसलिए हम लोगों की एक प्रकार से कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी भी है उनको जीवित रखने की। इसलिए इतना बड़ा रिकैपिटलाइजेशन

प्लान कि 2 लाख 12 हजार करोड़ रुपया बैंकों के अंदर डाला जाए और पब्लिक सैक्टर बैंकों को हम बनाए रखें, इसके पीछे उद्देश्य केवल यही है कि बैंक की जो क्षमता है विकास को सपोर्ट करने की, ग्रोथ को सपोर्ट करने की, वह अपने आप में कमजोर न पड़े। यह जो reckless spending हुई, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट भी हुआ, उससे बैंक की क्षमता ग्रोथ को सपोर्ट करने की, विकास को सपोर्ट करने की अपने आप में एडवर्सली इफेक्ट हुई है और उस कमजोरी से जूझते हुए उसका भी असर उस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर हुआ है, जिसको लेकर आप अपनी टिप्पणी कर रहे थे और इसलिए उन बैंकों की उस क्षमता को हमने बढ़ाया है। इसी तरह से सरकार की जो योजनाएं रही हैं, आपने कहा कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट, इस साल तो दस लाख करोड़ से ज्यादा की एग्रीकल्चरल क्रेडिट है और उसका ऑफटेक हो रहा है, जो बैंकों की तरफ से दिया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत साढ़े सात, आठ करोड़ लोगों को ट्रांजेक्शंस किए गए हैं, जिसमें छोटे-बड़े लोन छोटे उद्योगपतियों को दिए जाएं, जिसको हम इनफॉर्मल सैक्टर कहते हैं। उस इनफॉर्मल सैक्टर का इस परिस्थिति में उसके ऊपर असर न पड़े। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं अभी तक आंकड़े देखता रहा हूं। कई बार हम लोग यह टिप्पणी बार-बार कर देते हैं कि जी0एस0टी0 का स्मॉल सैक्टर के ऊपर क्या असर पड़ा है। हम लोगों को यह लगा कि छोटे उद्योग के ऊपर असर पड़ सकता है, तो उसी वक्त जी0एस0टी0 काउंसिल ने जो कम्पोजिशन स्कीम बनाई कि आज जिसकी ट्रांजेक्शन एक करोड़ तक है, वह एक परसेंट उस ट्रांजेक्शन के ऊपर देकर अपनी टैक्स लॉइअबिलिटी कम्पाउंड कर सकता है।

(3S/GS पर जारी)

KS-GS/3S/5.20

श्री अरुण जेटली (क्रमागत) : वन परसेंट की टैक्स लेवी, यह रेट तो शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा, जो छोटे और लघु उद्योग को दिया गया है और जिसका एक करोड़ तक का टर्नओवर है। अब काउंसिल ने यह कहा है कि इस एक करोड़ की सुविधा को डेढ़ करोड़ तक ले जाया जाएगा। This is the last recommendation of the Council. यानी जिसकी डेढ़ करोड़ तक की, people with one-and-a-half crore rupees transaction pay just one per cent for compounding itself. कई ऐसे आइटम्स हैं, जिनको बाहर रखा गया है। सैक्शन 94 में जो lowest charge mechanism था, कुछ छोटे लोगों को लगा कि इसका हम पर असर पड़ेगा, तो उसके बारे में ऑपरेशनल काउंसिल ने कहा कि हम बैंच में रखते हैं। यह जो बार-बार कई चीज़ों पर हम लोगों का तकिया कलाम बन जाता है, तो compounding का अभी तक टोटल टैक्स जितना आया देश में, जिससे लगा कि इसमें टैक्स से सारा स्माल स्केल इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा असर पड़ा और कई बार हम लोग नारे के रूप में इसको कह लेते हैं और फिर फिल्मों का डायलॉग इस्तेमाल करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें 16 लाख उद्योगों ने रजिस्टर किया है और उन्होंने टोटल ढाई सौ करोड़ रुपया जमा कराया है। इसलिए कितना adverse असर आया होगा, उस एक परसेंट बेसिस पर पूरे देश के अंदर, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप लोग करते

हैं। एक स्थिति बन गई थी कि किस स्थिति में इसको ले जाना है? Highway sector एक booming sector था, highway sector में यह स्थिति थी कि टेंडर भेजिए, कोई टेंडर का जवाब देने को तैयार नहीं था। आज 255 highways under construction हैं। रूरल रोड्स - कोई भी सांसद, विशेष रूप से लोक सभा के सांसद हैं, उनके ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आज राज्य सरकारों के साथ मिलकर, राज्य की सरकार मैं इसलिए कह रहा हूं कि ग्राम सड़क योजना का पैटर्न two-third: one-third है, 27-28 हजार करोड़ रुपया हर साल ग्राम सड़क योजना के अंदर जा रहा है और आप उस दिशा में जा रहे हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और physical infrastructure तथा जितनी भी social sector schemes आपके ज़माने से भी शुरू हुई थीं, कोई ऐसी नहीं जिसमें एक रुपया कम न हो, सरकारी साधनों के मुताबिक एक न एक नम्बर उसका बढ़ता रहा है। मैं फिर, भी कहूंगा कि आपने ठीक कहा कि इस देश की एक खूबी है और उसे मैं इस देश की एक ताकत मानता हूं कि even at a good seven to eight per cent growth rate, India is not a satisfied nation. We are not satisfied even if we are the highest in the world; we aspire for more. That is an aspirational India and that is a good sign. इसलिए जितने कदम हम लोगों ने उठाये हैं, उनमें कई कदम ऐसे थे, जिनकी शॉर्ट टर्म्स में हम लोगों को कीमत देनी पड़ी, लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मीडियम और लॉंग टर्म में इनका असर इस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर देखने को मिलेगा और आने

वाली पीढ़ियां यह याद रखेंगी कि इन कदमों से एक नया आर्थिक इतिहास इस देश का लिखा गया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Messages from Lok Sabha.

MESSAGES FROM LOK SABHA

(i) **THE NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 2018**

(ii) **THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (AMENDMENT) BILL, 2018**

SECRETARY-GENEREL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(i)

"In accordance with the provisions of rule 101 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that the following amendment made by Rajya Sabha in the National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2017 at its sitting held on the 2nd January, 2018, was taken into consideration and agreed to by Lok Sabha at its sitting held on the 4th January, 2018:-

CLAUSE 1

1. That at page 1, line 4, ***for*** the figure "2017", the figure "2018" be ***substituted.***"

(ii)

"In accordance with the provisions of rule 101 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that the following amendment made by Rajya Sabha in the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017 at its sitting held on the 2nd January, 2018, was taken into consideration and agreed to by Lok Sabha at its sitting held on the 4th January, 2018:-

CLAUSE 1

1. That at page 1, line 3, ***for*** the figure "2017", the figure "2018" be ***substituted.***"

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, we will take up Statutory Resolution and The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Bill, 2017. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल : सर, नहीं, नहीं। देखिए, पहले यह तय हुआ था कि हमारे अमेंडमेंट्स जो हुए हैं, जो अमेंडमेंट्स आपने accept किए हैं, उन अमेंडमेंट्स पर आप वोटिंग कराइए। आप उन पर वोटिंग कराइए और हम डिवीज़न की मांग करेंगे। आप

हम लोगों के अमेंडमेंट्स को पढ़िए, जो आपने accept किए हैं। आप उनको रखने के लिए बाउंड हैं। मैंने आपसे कहा है कि रूल 131 में यह आपका अधिकार है।

(HMS/3T पर जारी)

KGG-HMS/3T/5.25

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : यह गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है कि गवर्नमेंट क्या बिजनेस लाएगी। यह with the consent of the Chair है. इसलिए आप यह प्रथा खराब न करिए। हमारा, सुखेन्दु शेखर राय और आनन्द शर्मा जी का अमेंडमेंट Select Committee के लिए जो आपने accept किया है, आप उसे प्रस्तुत करें जिस से कि उस पर पूरे सदन की राय मालूम हो जाए।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Thereafter, we can go to the next Business. It will not take much of your time. ...(Interruptions)... We are serious in running the House. Don't create a situation where all the Business goes *topsy turvy*. ...(Interruptions)... Please do the needful. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल : सर, ऐसा न करिए कि सदन 11 बजे तक के लिए स्थगित हो जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now the hon. Leader of the Opposition, please.

नेता विरोधी दल (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : सर, सब से पहले मेरा आप से निवेदन होगा कि चेयर की नज़र या तो राइट होती है, सेंटर होती है और लेफ्ट तो होती नहीं।

قائد حزب اختلاف (شری غلام نبی آزاد): سر، سب سے پہلے میرا آپ سے نویدن ہوگا کہ چئیر کی نظر یا تو رائٹ ہوتی ہے، سینٹر ہوتی ہے اور لیفٹ تو ہوتی نہیں۔

श्री उपसभापति : मैंने इसीलिए आपकी ओर देखा।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : सर, मेरी आप से request है कि हम इस का समाधान निकाल सकते हैं, कल से बने गतिरोध का हमारे पास समाधान है। हम सरकार की मदद कर रहे हैं। हम एक दफा फिर स्पष्ट करना चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं से संबंधित जो बिल लाया गया है, उस ट्रिपल तलाक को, जो तुरंत तलाक होता है, फौरी तलाक होता है, instant tripple talaq होता है, उसके हम सब खिलाफ हैं। एक भी सदस्य उसके सपोर्ट में नहीं होगा, लेकिन अगर यह बिल लाया गया है और जैसा कि सरकार 24 घंटे टेलीविजन पर प्रचार कराती है कि ये मुस्लिम महिलाओं के बड़े हितैषी हैं, सपोर्टर हैं, लेकिन इस में जो प्रावधान है, वह मुसलमान महिलाओं को खत्म करने के लिए लाया गया है ...(व्यवधान)..

شری غلام نبی آزاد: سر، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم اس کا سمادھان نکال سکتے ہیں، کل سے بنے گتی رودھ کاہمارے پاس سمادھان ہے۔ ہم سرکار کی مدد کررہے ہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم مہیلاؤں سے متعلق جوبل لایا گیا ہے، اس ٹرپّل طلاق کو، جو تورنت طلاق ہوتا ہے، فوری طلاق ہوتا ہے، instant tripple talaq ہوتا ہے، اس کے ہم سب خلاف ہیں۔ ایک بھی ممبر اس کے سپورٹ میں نہیں ہوگا، لیکن

اگر یہ بل لایا گیا ہے اور جیسا کہ سرکار 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پر پرچار کراتی ہے کہ یہ مسلم مہیلاؤں کے بڑے ہتیشی ہیں، سپورٹر ہیں، لیکن اس میں جو پراؤدھان ہے، وہ مسلمان مہیلاؤں کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا ہے---(مداخلت)---

श्री प्रभात झा : आप मुस्लिम महिलाओं का अपमान कर रहे हो। ..(व्यवधान)..

श्री गुलाम नबी आज़ाद : उनके पतियों को जेल में डालकर ..(व्यवधान).. जब तक पति जेल में रहेगा, उसे कौन खिलाएगा, उसका खर्चा कौन बरदाश्त करेगा ...

شری غلام نبی آزاد: ان کے پتیوں کو جیل میں ڈال کر ---(مداخلت)--- جب تک پتی جیل میں رہے گا، اسے کون کھلائے گا، اس کا خرچہ کون برداشت کریگا۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't go into the merit or demerit of the Bill.

श्री गुलाम नबी आज़ाद : उसके बच्चों को कौन देखेगा? ..(व्यवधान)..

شری غلام نبی آزاد: اس کے بچوں کو کون دیکھے گا؟ ---(مداخلت)---

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Leader of the Opposition, please don't go into the merits of the Bill.

श्री गुलाम नबी आज़ाद : सरकार यह प्रावधान करे कि जब तक वह जेल में है, उसका खर्चा सरकार देगी। हम अभी सपोर्ट करते हैं ..(व्यवधान)..

شری غلام نبی آزاد: سرکار یہ پراؤدھان کرے کہ جب تک وہ جیل میں ہے، اس کا خرچہ دیگی۔ ہم ابھی سپورٹ کرتے ہیں---(مداخلت)---

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me now listen to the Leader of the Opposition.

श्री गुलाम नबी आज़ाद : उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि या तो आनन्द शर्मा जी का सुझाव मानिए या श्री देरेक ओब्राईन का सुझाव मानिए या सरकार यह सुझाव लाए, हम सरकार का सुझाव मानेंगे। इसे Select Committee को भेजा जाए। We are not standing on prestige.

شری غلام نبی آزاد: اس کے لیے کوئی پراؤدھان نہیں ہے۔ اس لیے میرا سجھاؤ ہے کہ یا تو آنند شرما جی کا سجھاؤ مانیئے یا شری ڈیرک اوبرائن کا سجھاؤ مانیئے یا سرکار یہ سجھاؤ لائے، ہم سرکار کا سجھاؤ مانیں گے۔ اسے سلیکٹ کمیٹی کو بھیجا جائے۔ We are not standing on prestige.

श्री उपसभापति : ऑनरेबल लीडर ऑफ दि हाउस।

नेता सदन (श्री अरुण जेटली) : उपसभापति जी, कल जब यह चर्चा आरंभ हुई थी, तो दो प्रस्ताव आए थे - एक श्री आनन्द शर्मा जी का और दूसरा श्री सुखेन्दु शेखर राय का। मेरा यह कहना था कि दोनों नियमों के मुताबिक नहीं हैं और इसलिए मैंने कल भी आग्रह किया था कि मैंने जो objection raise किया है, मैं चेयर से रूलिंग मांगता हूं कि Please rule on the validity of these motions. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give the ruling. ...(Interruptions)...

Please listen to the Leader of the House. ...(Interruptions)...

SHRI ARUN JAITLEY: I don't know the reason. यह बहुत स्पष्ट है कि जो प्रस्ताव आए, वे motions 24 घंटे पहले आने चाहिए थे। They did not come.

(Contd. By KGG/ASC/3U)

KGG-ASC/3U/5.30

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why are you doing this? ...(Interruptions)... बोलने दो ...(व्यवधान)... कहने दो ....(व्यवधान)... Please sit down. ...(Interruptions)... Dr. Subbarami Reddy, please sit down. ...(Interruptions)... आप बैठिए।

If the hon. Leader of the House is raising a point, the Chair will listen and reply to him. You need not interrupt like this. You allow me to conduct the Business of the House.

श्री नरेश अग्रवाल : सर, मेरा प्वॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: After this, please. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल : सर, मेरा प्वॉन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि अगर चेयर की रूलिंग पर ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will reply to that. आप क्यों reply करते हैं, मैं reply करूंगा। ...(व्यवधान).....

श्री नरेश अग्रवाल : चेयरमैन की रूलिंग पर ...(व्यवधान).....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give the ruling. ...(Interruptions)... Let me speak. Why are you doing this?

श्री अरुण जेटली : नरेश जी, ने बात शुरू की, तो नरेश जी हजारों प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर्स उठा चुके हैं, इसलिए इनको बहुत समझ है, तो इसलिए ये उस ज्ञान में ऐड कर लें।

My first objection besides the delay is that the Resolution says, 'I am orally giving some names, other names may be taken.' This is not a valid Resolution. The Parliamentary precedent is very clear. ...(Interruptions)... Sir, I am addressing you. It is of 1953 and I will give you the copy of the precedent: 'The Select Committee has to be one which represents the character of the House.' Therefore, both the resolutions have proposed a Select Committee which does not reflect the character of the House. ...(Interruptions)... This is very clear if you read Kaul & Shakdher: "The composition of a select committee or a joint committee reflects the strength of various parties and groups in the House. In that sense, the committee is a microcosm of the House or the Houses." So, any Committee where only one-sided names are given is not a valid Select Committee.

SHRI ANAND SHARMA: That is not true.

SHRI ARUN JAITLEY: Secondly, Sir, a Select Committee—this is a serious objection—is to work on legislation, improve on the legislation and report to the House. Now it is very clear from what the Leader of the Opposition has said. He said that most of the people are opposed to this Bill. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: We are not opposed to the Bill but to the contents of the Bill. ...(Interruptions)...

नेता विरोधी दल (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : आप टेलिविजन पर तो बोलते हैं ...(व्यवधान)... हमने कहा कि केवल तलाक के खिलाफ हैं....(व्यवधान)... क्योंकि इसमें जो एंटी वीमेन प्रावधान हैं ....(व्यवधान)....उनके खिलाफ हैं। ....(व्यवधान)... हम बिल के हक में हैं....(व्यवधान)...जो प्रावधान हैं....(व्यवधान)... जब तक उसका पति जेल में है तब तक उसको कौन खिलाएगा? ....(व्यवधान)...हम उस प्रावधान के खिलाफ हैं। ...(व्यवधान)...

قائد حزب اختلاف (شری غلام نبی آزاد): آپ ٹیلی ویژن پر تو بولتے ہیں ---(مداخلت)--- ہم نے کہا کہ صرف طلاق کے خلاف ہیں ---(مداخلت)--- کیوں کہ اس میں جو اینٹی ویمین پراؤدھان ہے---(مداخلت)--- ان کے خلاف ہیں---(مداخلت)--- ہم بل کے حق میں ہیں---(مداخلت)--- جو پراؤدھان ہیں---(مداخلت)--- جب تک اس کا پتی جیل میں ہے تب تک اس کو کون کھلائے گا؟ ---(مداخلت)--- ہم اس پراؤدھان کے خلاف ہیں---(مداخلت)---

श्री उपसभापति : ऑनरेबल LoP आप बैठिए। ....(व्यवधान).... बैठिए, बैठिए। ..(व्यवधान).....

श्री गुलाम नबी आज़ाद : हम बिल के हक में हैं ...(व्यवधान)... लेकिन उसके पति के जेल में रहने पर कौन खिलाएगा, इसका कोई प्रोविजन नहीं है। ...(व्यवधान)....

شری غلام نبی آزاد: ہم بل کے حق میں ہیں ---(مداخلت)--- لیکن اس کے پتی کے جیل میں رہنے پر کون کھلائے گا، اس کا کوئی پرووِیژن نہیں ہے ---(مداخلت)---

श्री उपसभापति : स्मृति इरानी जी ..(व्यवधान)... आप लोग बैठिए, बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद : आप लॉ में यह प्रावधान रखिए कि जब तक उसका पति जेल में है, उसको खाना क्या सरकार खिलाएगी? ...(व्यवधान)...

شری غلام نبی آزاد: آپ لا میں یہ پراؤدھان رکھیئے کہ جب تک اس کا پتی جیل می ہے، اس کو کھانا کیا سرکار کھلائے گی؟ ---(مداخلت)--

श्री उपसभापति : गुलाम नबी जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान)... हम बिल के हक में हैं। ...(व्यवधान) .....Let me deal with this. ...(Interruptions)... I will give the ruling after this. ...(Interruptions)... Allow him to say and I will give the ruling. What are you doing? What is this? ...(Interruptions)..

(Followed by SSS/3W)

SSS-KLG/3W/5.35

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, the second practice is, besides the delay none of the two resolutions is representative. The second principle is, a saboteur to a Bill can never be on the Select Committee. Those who seek to sabotage a Bill and this is held in a Parliamentary ruling of 1958.. ...(Interruptions)... अगर आप बिल को सेबोटेज करना चाहते हो, तो आप सेलेक्ट कमेटी से डिसक्वालिफाइड हो, यह पार्लियामेंटरी प्रोसीजर है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please sit down. ...(Interruptions)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Sir, how can you allow this? ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me speak. ...(Interruptions)... I have to give a ruling on this. ...(Interruptions).... This is what I said.

SHRI ARUN JAITLEY: You are trying to sabotage the Bill. You can't be in the Select Committee. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to give the ruling. ...(Interruptions)... I am only asking you a question.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, the Leader of the House has challenged my motion. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I am saying. Let me give the ruling on that. I want to give the ruling.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: The Leader of the House has challenged the technicalities of my motion. So, I should be given an opportunity of hearing. It relates to my motion. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will. Either you listen to me or else I will have to adjourn the House. ...(Interruptions)... I will have to adjourn the House if you so want. It is because the hon. Leader of the House has raised a question on the very issue on which yesterday I gave a decision. Therefore, I am bound to give a reply to that. First you have to allow me. After that I will allow you. ...(Interruptions)... Yesterday I said that both the motions have been accepted and it is valid. Now, I have to explain why it is so. I am not disputing anything on what hon. LoH has said. I am not disputing. One point he said is that, one resolution is not representative ...(Interruptions).. Let me complete. ...(Interruptions)... Hon. LoH said, one amendment does not contain names from all the sides. He has read that.

SHRI ANAND SHARMA: That is not true.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am saying what he said.

श्री नरेश अग्रवाल: सर, आप बोलिए। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am saying what he said.

श्री नरेश अग्रवाल: आप बोलिए, सर।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can't even listen to that. I am saying what he said. ....(Interruptions)... The second thing is 24 hours' notice is required. That way it is valid. The third thing he said is that Shri Sukhendu Sekhar Ray's resolution does not contain the names.

SHRI DEREK O'BRIEN: Of course, it contains and we will tell you why.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, fine, I will come to that, but what I said yesterday is, I heard all of that. I am not disputing anything. What I said yesterday was something else. I will repeat that and I will explain the rationale also. Number one, I said the two amendments have been accepted and admitted by the hon. Chairman. If there is technical defect in an amendment, the Secretariat should have seen to it.

(Contd. by NBR/3X)

-SSS/NBR-AKG/3X/5.40

MR. DEPUTY CHAIRMAN (CONTD.): Therefore, I presume, since the hon. Chairman has admitted it, that it is an admitted resolution. This is number one. ...(Interruptions)...

SHRI T.K. RANGARAJAN: So, now, we want a Division.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sit down. ...(Interruptions)... Then, you come here and decide. ...(Interruptions)... I am also a human being.

Secondly, with regard to the question of 24 hours or one day's notice, Rule 232 is clear. The same rule says and I read it. It says, "Notice of an amendment to a motion shall be given at least one day before the day on which the motion is to be considered, unless the Chairman allows the amendment to be moved without such notice." Here, the hon. Chairman allowed. Therefore, the Deputy Chairman has no role to change it; I cannot change it.

Third one is the most important point. Here, I crave your indulgence. All of you should listen to it. Why I took a decision? Why I said that? I heard the hon. Leader of the House. I know he is a legal luminary. Whatever he said has relevance. I admit it. But, I cannot accept and act on that. Or, I could not do that. I will tell you the reason why. The rule clearly says that the amendment is a motion. The amendments moved by Shri Anand Sharma and Shri Sukhendu Sekhar Ray are amendments and are motions moved in the House. If the hon. Chairman admitted a motion, I have no go other than allowing it to move. Secondly, motion is moved. And, once motion is moved, it is the property of the House. The Chair, whoever may be sitting on the Chair, has no role in that. But, whatever the Leader of the House said is valid. It is for the House to listen to that and

take a decision. The Chair cannot take any decision. Once a motion is moved, it is the property of the House. I cannot ask him to withdraw the motion or I cannot amend that motion. Only this House has the prerogative to amend that motion. Therefore, both motions are here. It is up to the House, after listening to what he said, to decide. ...(Interruptions)... It is my decision. ...(Interruptions)... This is my position. ...(Interruptions)...

Regarding the question of taking up of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, I have already said that I did not give any decision or direction yesterday. So, it is the priority or prerogative of the Government to list it and the Government has listed it in a different way and it is within its right to do that. Therefore, I cannot take up that Bill now unless the Government also agrees or unless there is consensus in the House. That is the position.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, you had said that you would allow me, since my name has been mentioned. ...(Interruptions)... I am the mover of the resolution.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : डिप्टी चेयरमैन सर, मेरी हाउस से request है कि गवर्नमेंट ने जो List of Business दी है, उसके अन्दर GST (Amendment) Bill को लिया जाए। उस पर गवर्नमेंट कायम है। ...(व्यवधान)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, you said, ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am taking up the Goods and Services Tax (Amendment) Bill.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, please hear me first. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, this is to be decided first.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, first of all, I want to repeat and place it on record so that nothing wrong is recorded. Yesterday, when I moved the resolution, I also said, on both the occasions i.e., when I was speaking and given in writing, the names of the BJP and the NDA shall be given by the Government -- it is in writing -- along with the names from the Opposition.

(CONTD. BY PK/3Y)

PK-SCH/PB-RPM/3Y & 3Z/5.45 -5.50

SHRI ANAND SHARMA (CONTD.): To say that the composition is.....(Interruptions).. This is not correct. It is given in writing.

Secondly, Sir, Rule 131 is also there. The unfinished Business has to be finished.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: For that, I gave the ruling.

SHRI ANAND SHARMA: The motions have been moved. Yesterday, the Government, the Ministers, the Ministers who are not even Members of

Rajya Sabha, were disrupting. ..(Interruptions)... Now, that has to be finished.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That I have decided.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, with all respect to the Chair, we are very clear if the Government, as the LoP has said.....(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: For that, there should be a consensus. I have decided that.

SHRI ANAND SHARMA: If the Government wants a consensus, we can resolve it in two minutes. If the Government does not want....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You do one thing. You can.....(Interruptions).. I have no.....(Interruptions).. I will now take up the GST Bill and you can....(Interruptions)..

SHRI ANAND SHARMA: You will not. ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. It is for the Government.....(Interruptions).. Okay. Shri Sukhendu Sekhar Ray, since you moved the motion, what do you want to say?

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, a question has been raised...(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I gave the ruling.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: No, no, Sir. I have to make one submission. A question has been raised by the hon. Leader of the House that the list which I have given in the motion does not hold a representative character. Now, the question is this. It was discussed in the Business Advisory Committee (BAC) and all party leaders said that the Bill should go to the Select Committee. And, the hon. Chairman says that because the Government is not willing.....(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is said there, you should not say. ..(Interruptions)..

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Then, the hon. Chairman says that since the Government is not willing, the matter will be decided in the House. Now, since the Government is not willing to refer the matter to the Select Committee, how can I give the names of the ruling party? This is number one. Number two and it is my final point, even now, if the Government wants that they should be represented, their party should be represented, I am open for that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. ..(Interruptions).. I have given the ruling. ...(Interruptions)..

SHRI DEREK O'BRIEN: Today, it has become pretty clear that this side wants to empower women and they have been exposed. ...(Interruptions)... They have been exposed. ....(Interruptions)..

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Absolutely not. ...(Interruptions).. We want to empower women but they don't. They want to ... ...(Interruptions)... I want a discussion now. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I have given the ruling. With regard to Government Business, the priority is for the Government to decide. The Government has listed the GST Bill. So, I cannot start the Bill on Triple Talaq. ...(Interruptions)... Statutory Resolution, Dr. Subbarami Reddy. ....(Interruptions)... Dr. Subbarami Reddy, are you moving? ...(Interruptions)... I have given the ruling. I cannot take up the Bill on Triple Talaq now because there is no agreement. There is no consensus. ...(Interruptions)... That is not listed first in the Business. So, we cannot take it up. ...(Interruptions)... With regard to the Government Business, the priority is for the Government to decide. So, I cannot do that. ...(Interruptions)... No. No. ...(Interruptions)... The GST (Amendment) Bill. ...(Interruptions)...

The House is adjourned till 11.00 a.m. tomorrow, Friday, the 5th January, 2018.

The House then adjourned at forty-nine minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 5th January, 2018.